THE UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 1970—*contd.*

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, हम को इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि उस दिन यह विवाद समाप्त होने ज रहा था और मंत्री जी अंतिम जवाब करने जा रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपने को समाजवादी और जनतंत्रीय कहती हो उस सरकार की दृष्टि क्या होनी चाहिए। आज उस सरकार को समाजवादी और जनतंत्रीय नहीं मानना चाहिए जो सरकार कि जो जितना पिछड़ा हो उस को विशेष अवसर दे कर उतनी ही ज्यादा सहायता अगर न करे। इस समय भारतवर्ष में अगर कोई समान सहायता का सिधांत चलायेगा तो मैं उस को समाजवादी नहीं मानता। मैं उस को एक रिफाइन्ड बुर्जुआ कहने के लिए तैयार हो सकता हूं, लेकिन अच्छा सामाजवादी वही है कि जो श्री के० के० शाह साहब के कान में अपनी बात को ठीक से पहुंचा दे और श्री के० के० शाह साहब उस को ठीक से सुनें। आज इस देश के समाजवादियों का प्रथम, बुनियादी कर्तव्य यह होना चाहिए कि श्री के० के० शाह साहब के कान में अपनी बात को बाज़ाबता तौर पर पहुंचा दें मगर यूनस साहब उन को सुनने नहीं देंगे क्योंकि समाजवाद और यूनस साहब में परस्पर विरोध है। तो मैं कह रहा था कि समाजवाद के मायने क्या ? यह प्रश्न केवल देश के पैमाने पर नहीं, बल्कि विश्व के पैमाने पर मैं चालू करना चाहता हूं। जो जितना ही धनी मुल्क हो उस से उतना ही ज्यादा लिया जाय और एक विश्वकोष बनाया जाय और उस से जितना ही गरीब मुल्क हो, पिछड़ा हो उस को उतनी ही ज्यादा सहायता दी जाय। यह चीज आज की समाजवादी और जनतंत्रीय पद्धति की प्रणाली होनी चाहिए। मगर यदि भारत सरकार की तथाकथित, सोकाल्ड प्रोग्रेसिव जो अपने को कहती है, इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि उस ने देश में समान अवसर के सिधांत को अपनाया है या विशेष अवसर के सिद्धांत को अपनाया है। मैं समझता हूं कि यहां समान अवसर का सिद्धांत चल रहा है। एक आबादी मान ली गयी और उस आबादी के अनुपात में एक्साइज ड्यूटी को वितरित करने का प्रयत्न किया गया राज्यों में। यही है न ? क्यों ? लेकिन मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राज्य है जिस उत्तर प्रदेश को अंग्रेजों ने जानबूझ कर पिछड़ा रखा। अंग्रेज साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगुवायी करते रहे हैं, आगे रहे हैं। 1857 में जो पहली सरकार विरोधी क्रांति हुई वह उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। इस लिए अंग्रेज चाहते थे कि चाहे जो हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पीछे रहे और इस लिए उस के विकास का कोई काम नहीं किया गया। जितना विकास बंगाल में कलकत्ता का हुआ बंबई या मद्रास का हुआ उतना उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ और इसी लिए आज भी कांग्रेस की सरकार, श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी की सरकार, जो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी पदचिन्हों पर चल रही है, उस रास्ते से अपने को हटाना नहीं चाहती। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर वह समुचित रूप में संघ उत्पादन शुल्क का वितरण करना चाहते हैं तो यह लाजिक न होगी कि जहां के लोग पिछड़े हैं उन को उस के अनुरूप सहायता न दी जाय। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की आबादी 9 करोड़ की होने जा रही है। तो 9 करोड़ की आबादी जहां पर हो और उस में आधे से ज्यादा दोनों जून खाना न खाते हो, जहां पर ऐसे इलाके हों कि वहां के लोगों को पूरा बदन ढकने को कपड़ा न मिलता हो, जहां के लोग आज भी जाड़ों में पुआल के अंदर घुस कर सर्दी काटते हों, ऐसे लोगों को विशेष ढंग से, विशेष सुभीता देने के लिए संघ उत्पादन शुल्क का वितरण क्यों न हो? इस को मद्देनजर क्यों न रखा जाय। इस अवसर पर मुझे अफसोस है कि लोग कहेंगे कि यह संघ उत्पादन शुल्क क्यों वितरित हो रहा है, मगर मैंने चाहे वह संघ उत्पादन शुल्क हो, चाहे प्लानिंग की पूरी निधि हो, सदा कहा है कि उस के लिए हम को एक दृष्टि चाहिए। हम को एक पथ चाहिए। क्या वह

दृष्टि सरकार के पास है ? वह दृष्टि हम देखते हैं कि नहीं है। इस लिए मैं आज जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर पिछड़े हुए राज्य हैं उन राज्यों की स्थिति को विशेष रुप से मद्देनजर रखा जाय और विशेष अवसर का सिद्धांत मान कर, जो भारतवर्ष में एक आम समाजवादी पद्धति होगी, उस के मुताबिक सारी आय का वितरण किया जाय।

श्रीमन्, आप जानते होंगे और सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य जानते होंगे और हमारे नवाब साहब, अकबर अली साहब तो जरूर जानते होंगे कि हम चौखम्भा राज का सिद्धांत मानते हैं। आज इस सरकार की जो टैक्सेशन प्रणाली है, इस का कर लगाने का जो सिस्टम है उसको मैं पूर्णतया दोषपूर्ण मानता हूं। जब बजट आयेगा तो आप देखेंगे--उस मौके पर मैं रह पाऊंगा या नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि 200 करोड़ के ऊपर श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी की तथा-कथित प्रतिक्रियावादिता नये टैक्स लगा रही है और उस दो सौ करोड़ में केवल धनिकों पर 30 करोड़ के करीब पड़ेगा और बाकी 170 करोड़ के करीब आम जनता पर जायेगा। यह इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन होगा। मैं आज जानना चाहता हूं श्री के० के० शाह साहब से, जो इस सदन के बाहर भी कभी कभी मुझ को मिल कर सलाह देने की कोशिश करते रहते हैं कि यह समाजवाद है कि जो सरकार परोक्ष, इन्डाइरेक्ट टैक्स बढ़ाती चली जाय, उस सरकार को कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाजवादी व्यवस्था में आस्ता रखने वाला राजनीतिक क्या समाजवादी कहेगा ? अगर वह उसे समाज वादी कहता है तो वह समाजवादी की मृग मरीचिका में फंसता है। वह समाजवाद नहीं है। वह शुतुर्मुर्ग की स्थिति में है, वह पूंजीवाद की बालू में सिर गाढ़ देता है और समझता है कि उस को कोई देख नहीं रहा है। मगर जिन की दृष्टि पैनी है, जिन की नजर तेज है वे इन बातों को ठीक से देख रहे हैं कि आज भारतवर्ष की सरकार एक विकृत पूंजीवाद की व्यवस्था को चला रही है। इस सरकार में तनिक भी समाजवाद का अंश हो तो मैं कहना चाहूंगा कि य सरकार चौखम्भा राज के सिद्धान्त को माने। चौखम्भा राज का अर्थ क्या है ? आज सरकार दो खम्भों पर टिकी हुई है एक खम्भा है केन्द्र और एक खम्भा है राज्य। इस के बाद राजकीय शक्ति और कहीं नहीं है। कानून बानने की शक्ति कहीं नहीं है। इस के बाद डेलीगेशन आफ पावर है, पावर का हस्तांतरण है, चाहे वह जिला परिषद् के नाम पर हो, चाह वह गांव पंचायत के नाम पर हो या वह गांव सभा के नाम पर हो, मगर राज्य तो दो ही हैं--एक है दिल्ली, एक है लखनऊ, दिल्ली पटना, दिल्ली भुवनेश्वर, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली बंबई, दिल्ली मद्रास। तो इस तरह राज्य दो हैं, मगर इन दोनों का रिश्ता भी खराब हो रहा है। यह संघ क्या है। यूनियन आफ स्टेट्स है, अकबर अली खान साहब। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अकबर अली खान साहब से कहना चाहता हूं, चूंकि वह संविधान को जानते हैं। तो यह यूनियन आफ स्टेट्स है, यह राज्यों का संघ है। यह नहीं है कि संघ एक मर्तबा बन जाय और बन कर के कुछ अपने हिस्सों को बांटे। यह राज्यों का संघ है, पर राज्य और संघ का रिश्ता आज खराब हो रहा है और उस खराबी की एक नजीर श्री लोकनाथ मिश्र ने अभी दी।

(समय की घंटी)

मैं अपने आप खत्म करूंगा, अगर आप घंटी बजायेंगे तो शायद देर हो जायेगी। आपकी घंटी को सुन कर जो पाइंट मैं कह रहा हूं वह कुछ दूर होने लग जाता है।

श्रीमन् मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर आज सम्पूर्ण ढांचा इस सरकार के बूते का नहीं है कि बदला जाय तो कम से कम चौखम्बा राज्य के सिद्धान्त को टैक्स प्रणाली में तो अमल में लाये और जैसा कि हमारा कहना था कि केन्द्र के पास केवल विदेशी मामले रहें, देश की सुरक्षा के सवाल रहें और अन्तर-राज्यों के मामले रहें, इसके अतिरिक्त केन्द्र के पास और ज्यादा ताकत नहीं रहनी चाहिये, राज्यों के पास अपने राज्य

[श्री राजनारायण]

से सम्बन्धित सभी बातें रहें और जिले और गांव के पास उससे सम्बन्धित सभी बातें रहें। गांव पंचायत, जिला पंचायत, राज्य पंचायत और केन्द्र-पंचायत-राज ये चार पाये स्टेट के हों इन्हीं चार पायों पर सारी आर्थिक व्यवस्था बिखरी हो, यह जनतंत्र होगा सेठी साहब। जनतंत्र एक शब्द नहीं है, जनतंत्र एक व्यवस्था है, जनतंत्र एक ढांचा है, जीवन के सर्वांगीण अवयवों को परिवर्तित करने का एक नुस्खा है। जनतंत्र एक शब्द नहीं है कि हम कह दें कि हम जनतंत्री हैं। इन्दिरा गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं, गांव गांव छितराई है--यह नारा लगा हुआ है, इससे जनतंत्र नहीं आयेगा और न गांव में नई कोई रोशनी आ रही है, अगर कोई नई रोशनी गांव में जा रही है तो भ्रष्टाचार की जा रही है, सत्ता हथियाने की जा रही है, झूठ बोलने की जा रही है जिससे हमारा देश आज भ्रष्टाचार के गर्त में जा रहा है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जरा इस पर सोचे नहीं तो सरकार अपने को जनतंत्री न कहे।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : आपको चकाचौंध में प्रकाश दिखाई नहीं देता :

श्री राजनारायण : अगर कोई महिला बोलना चाहती है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री विद्यावती चतुर्वेदी : मैं कह रही हूं कि चकाचौंध में, प्रकाश में चौंध लगता है इसलिए प्रकाश दिखाई नहीं देता ऐसे जन्तुओं को।

श्री राजनारायण : श्रीमती विद्यावती की टोकाटोकी को मैं बहुत पसन्द करता हूं। विद्यावती की जो टोकाटोकी होती है मैं उसको बहुत ही पसन्द करता हूं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : आपकी उलूक-वाणी उतनी ही पसन्द है मुझे।

श्री राजनारायण : मगर टोकाटोकी का नतीजा क्या है, मैं चाहता हूं कि उसके नतीजे से भी वह अपने को ओतप्रोत करायें। ऐसा नहीं कि केवल एक शब्द कह दें। आज श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के खोटे सिक्के की चमक में श्रीमती विद्यावती जी चौंध खा रही हैं, यह इसका नतीजा है।

श्री कृष्ण कान्त (हरियाणा) : चकाचौंध तो आप हो रहे हैं।

श्री राजनारायण : मैं चाहता हूं कि श्रीमती विद्यावती चौंध न खायें और जो हमारी समाजवाद की बात है उसको सुनें और उसे अमल में लाने की कृपा करें। क्या है!

श्री उपसभापति : आप समाप्त कर रहे हैं न अभी!

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपने फिर बोल दिया, हम बिल्कुल पांच मिनट में खत्म कर देते, आप न बोलें तो पांच मिनट में खत्म हो जायगा, आप बोल देते हैं तो दो मिनट और लग जाता है। मैं खत्म कर रहा हूं।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि श्री के० के० शाह भी समझें, सेठी साहब भी समझें और इन लोगों से श्रीमती विद्यावती भी समझें।

श्री कृष्ण कान्त : ओह, ओह।

श्री राजनारायण : देखिये, वह जननी हैं। ओह ओह क्या। वह जननी हैं। ओह ओह क्या बोल दिया।

बात यह है, अगर जनतंत्री है तो सारे रिसोर्सेज, सारे साधन, उत्पादन के साधन, विनिमय के साधन, वितरण के साधन—इसी को मैं अनुवाद करने लगूं तो देर लगेगी लेकिन अकबर अली खान साहब के लिये मैं अनुवाद करना चाहता हूं—मीन्स आफ प्रोडक्शन, मीन्स आफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन्स आफ एक्सचेंज, अगर ये सारे, राब, केन्द्रीय सरकार के हाथ में चले जायें तो क्या यह समाजवाद होगा, मैं अदब के साथ पूछना चाहता हूं श्री के० के० शाह साहब से! जो आज का वर्तमान युग है, अपने देश का युग है, उसके साथ धोखा न करो, अपने साथ धोखा न करो। सेठी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह समाजवाद होगा!

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : समझ गया जो आप कहते हैं।

श्री राजनारायण : अगर समझ गये तो तुरंत उसके मुताबिक काम करें। मैं वर्तमान विधेयक में उस दिन संशोधन रखना चाहता था, तो या तो इसको आप पास न होने दें या इसमें यह गुंजाइश कहीं रखें कि जो राज्य जितना ही पिछड़ा है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों से कम है, उसको भी मद्देनजर रखा जायगा आबादी के साथ साथ। आबादी रहे और उस राज्य का पिछड़ाव रहे, उस राज्य के पिछड़ाव को ध्यान में रखते हुये इस शुल्क का बटवारा हो वर्ना केवल समाजवाद और जनतंत्र नाम रह जायगा, यह व्यवहार में तो कभी आयेगा ही नहीं। राम का नाम ले लेंगे मगर व्यभिचार करते चले जायंगे। मंदिर में शंकर पर लोटे का दूध और जल चढ़ायेंगे और वहीं पर अपनी तिरछी नजर किसी दूसरे के चेहरे पर डालते रहेंगे, ये दोनों बातें बिल्कुल अशोभनीय हैं, यह नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो कथनी हो उसी के तदनुरूप करनी हो, बुद्धि और आचरण का मेल हो, के० के० शाह साहब बुद्धि के विपरीत आचरण भ्रष्ट हैं, आचरण के विपरीत बुद्धि छलना है और इसकी आज सब से बड़ी महारत जो विश्व में किसी को हासिल है तो वह है भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी को, उनसे बढ़ कर आज राजनैतिक भ्रष्टाचार की शिक्षा कोई पढ़ा नहीं सकता। नमस्कार।

SHRI B.T. KEMPARAJ (Mysore): Mr. Deputy Chairman, the Schedule to this Bill shows that only Rs. 4.65 crores has been proposed to be allotted to Mysore. Though the Fifth Finance Commission has allotted this amount, there is nothing to show that the Commission has made any improvement on the funds allotted because even the Fourth Finance Commission allotted the same amount. If we see the Schedule, we will find that the other States have got more money comparatively. I do not know why this step-motheriy treatment has been meted out to Mysore. The same principle does not seem to have been made applicable in respect of all the States. In regard to Mysore, there are hard-pressed conditions and the Mysore Government has made many requests to the Central Government to enhance the funds allotted under the Fourth Plan. When this matter had been pending with the Central Government, in spite of it, the Central Government has made up its mind to allot only this amount. I urge on the Government to see that an equitable amount is allotted to Mysore before the Bill is passed and it should be related to the allocations made to other States. The same principle as has been applied to other States must be made applicable to Mysore also. Proposals have been made that the per capita income must be taken into consideration while allocating the amounts. Another proposal has been made by some intends that the density of the population in the States must be taken into consideration. Therefore, on these two principles if the amount had been allotted, certainly Mysore would have got more share to 'its benefit. But as it is seen here, Sir, the picture is otherwise, because the same amount, which was allotted in the Third Five-Year Plan, cannot be the same in the Fourth Five-Year Plan also. There must have been the comparative rise in the case of Mysore as it is noticed in the case of other States. Therefore, what is the principle on which the same amount had to be allotted to Mysore State only? That is the point for consideration. I think the Government will consider this point of view and see that the proportional increase, as is noticed in the case of other States, is given to Mysore State also. Sir, even for the Fourth Five-Year Plan the Mysore Government has been urging for the enhancement of the allotment of funds for developmental works because of lack of financial resources for the purpose in the State's income. Though the Central Government often gives more amounts to several States because of

[Shri B. T. Kamparaj] their pressure, it is very unfortunate that the Central Government is not at all paying heed to the demand or the request of the Mysore Government. Whatever may be the request of the, State Government of Mysore, the Central Government, I have to say with great regret, is keeping silent and mum. But when the request or demand comes from other States, they react favourably and urgently, and this we can see in the allotment of funds, in the releases of excess funds from the Consolidated Fund and from several other funds, from flood relief fund and other things. Even on the last occasion, when there was the drought situation in Mysore, the Central Government, in spite of our repeated requests, was able to release only one crore odd of rupees, while to other States it has released greater sums. Therefore my particular request to the concerned Minister is to see that the grant under this head is raised proportionately. If not liberally or justifiably, let 'it be reasonably raised at least, let it be seen that this amount is properly raised, as properly as 'it is raised in the case of other States, so as to enable Mysore State to take up the developmental works and also see that the conditions of the people are thereby improved.

Thank you.

SHRI P.C. SETHI: Sir, the purpose of the Bill before this hon. House is very limited and it is—in terms of the Fifth Finance Commission's recommendations—the devolution of certa'in accurals to the Government of India in the form of excise duties to be distributed. Sir, hon. Members have raised the point that the Constitutional provision with regard to devolution of funds in our country is not adequate and requires a change. This may be a matter of opinion, but I would like to say that, as far as the Constitution is concerned, it has already provided for a number of things. For example, the duties mentioned in Article 268, although levied by the Government cf India, are collected and completely retained by the States, and the net proceeds of certain taxes mentioned in Article 269 are levied and collected by the Union but are entirely assigned to the States. Similarly, Sir, a percentage of the net proceeds of the inccme-tax which at the present stage is 75 per cent, of the total collection of the income-tax, is assigned to the States in terms of Article 270. Then Union Duties of Excise, which are levied and collected by the Government of India under Article 272, fall in the category of taxes which 'may be' distributed between the Centre and the States. Further Article 275 recognises the necessity for Grants-in-aid to revenues of States, which may be in need of assistance. Article 282 provides for grants by the Union to the States for any public purpose. Article 293(2) provides for loans being advanced by the Government of India to the State Governments. Now, Sir, as the position stands today, the various Finance Commissions' reports are before us and we can clearly see that from every Plan period to the next Plan period the amounts which were given by the various Finance Commissions to the State Governments have been going up, as was said by me earlier. Transfers under the Finance Commissions' awards had gone up from Rs. 386 crores during the First Plan period to Rs. 877 crores during the Second Plan period. Transfers during the Third Plan period amounted to Rs. 1549 crores, and in the period covered by the three subsequent Annual Plans (1966-67 to 1968-69) the transfers to the States went up to Rs. 1746 crores. The transfers during the Fourth Plan period (1969—74) are estimated by the Fifth Finance Commission to be Rs. 4,226 crores at th" W9-70 rates of taxation. Out of the additional taxation proposed for the next year at the Centre. Rs. 45.30 crores would accrue to the States. Thus, Sir, the position is very clear that from one Finance Commission to another, from one Plan period to another Plan period, devolution of the various funds from the Centre to the States has been mounting up. It has been also argued here that the fields which are left for taxation to the States are not elastic as compared

to the Centre. But it is not so. The position is this that the rise in the revenues of the State Governments iias been from about Rs. 360 crores in 1950-51 to Rs. 2502 crores in 1969-70, which gives an indication that in these twenty years there has been a seven-fold increase in the revenues of the State Governments, which is also equivalent to the seven-iold increase in the revenues of the Central Government. Therefore it is not quite correct to say that inelasticny is there or that the scope for taxation is not there. In fact, Sir, the Fifth Finance Commission has po n-ted out that resource mobilisation by the States has in some cases, been going down. For example, in 1966-67 the mobilisation was Rs. 40 crores, in 1067-68 it was Rs. 26 crores and in 1968-69 it was Rs. 18 crores, and that although m the year 1969-70 it was envisaged to be of the order of about Rs. 120 crores, it may come to Rs. 54.5 crores. Therefore, Sir, the Fifth nuance Commission itself has made a number of suggestions for resource mobilisation by the States, and the implementation of these recommendations is certainly a matter for the State Governments to consider. The Planning Commission and the Government of India have, from time to time, been requesting the State Governments that the resource mobilisation left at their end should be properly tackled and they should see to it that the requisite resources to finance their Plans may be raised by them. Sir, I would also like to point, out that the duties of the Centre are onerous and they have to cover a very large and overall field. For example, it has been said that the State Governments are directly in touch With the people of the States. It is true. Sir. that for very many matters the State Governments are in touch with the people of the States. But as far as the Centre is concerned, they have to take into account the question of defence. The defence expenditure was about Rs. 3300 crores for the entire Th'rd Plan period, and now, for one year, for the year 1970-71. the defence expenditure has been placed at Rs. 1152 n-oros. Similarly, there are other responsibilities of the Central Gov-

eminent, with regard to communications, national highways, railways and other things. Therefore it is not correct to say that the responsibilities of the Centre ate not over a wider area. They have to look to a much wider range of things and also look to the needs of the defence of the country. From this point of view I would only urge that it is not correct to say that the State Government had to come to the Centre w'ith a begging bowl for various types of assistance Cor their Plans and for the resources that they need. On the contrary this is a mere scientific and more I P.M. logical basis where not the Government itself decides but a body like the Finance Commission which is an independent body, which is a high-powered body, which goes to the States and discusses with them in detail all the requirements of the States with regard to their revenue expenditure and also with regard to their non-Plan expenditure and after giving careful consideration and thought to a'l these mathrs come to their conclusions and recommendations. These recommendations ought to be considered and have been considered to be more independent rather than Government itself coming to a decision as to what devolution of the resources from the Centre should go to the various States. And the practice has been that as far as the Finance Commission's recommendations are concerned they are almost treated as award and therefore the Government propose to treat the recommendations of this Fifth Finance Commission also as award. It has also been pointed out here by certain hon Mem-b?rs, particularly Mr. Rajnarain for example, with regard to TJ.P. . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Would von be taking longer time?

SHRI P.C. SETHI: I would finish in five minutes. Sir.

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa): The other Bill is also his and h" will be here "n the afternoon also. We can continue after lunch.

SHRI OM MEHTA (Jammu and Kashmiri: We ran finish this now in a few minutes and then take the other Bill after lunch.

SHRI P.C. SETHI: Just as you like. I am in your hands, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is also another Bill in your name and 1 was . . .

SHRI OM MEHTA: I would request you to give him five minutes. We can finish this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: AH right.

SHRI P.C. SETHI: Sir, I would not take much time of the House. I would only say that the Fifth Finance Commission has gone into all the aspects both with regard to revenue expenditure as well as non-Plan expenditure. I would urge that this Bill is orJy to regularise whatever the Fifth Finance Commission has recommended and put it in a legal form.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration".

The motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 tuere *added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. C. SETHI: Sir, I move: "That the Bill be returned".

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.00 P.M.

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the Clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

REFERENCE TO REPORT OF THE COMMITTEE WHICH ENQUIRED INTO THE AFFAIRS OF THE CSIR.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, I bring to your notice something which has appeared in the newspaper today. Some report purporting or claiming to be the findings of the Committee enquiring into the affairs ol the CSIR . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute please. Did you get permission from the Chair?

SHRI BHUPESH GUPTA: No, but just I have seen it.

SHRI LOKANATH MISRA (Oris-sa): He is a supernumerary of the Congress. Why should he ask for permission from anybody?

SHRI BHUPESH GUPTA: Has he taken permission?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI BHUPESH GUPTA: The report has to be submitted to Parliament. Now that report we have not received, but we read about it in the newspaper and it has said something about the Director of the institute or the CSIR Director-General or whatever it is. This is Very improper. The report should be laid on the Table of the House. I am told that they do not have enough copies. All right. Let the copies that are available be laid on the Table of the House. Sometimes we are not all given copies.

SHRI BIREN ROY (West Bengal): It will be done tomorrow.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is a very interesting thing. It seems they are briefing the press to make out a case for Dr. Atma Ram, saying that he has been given a clean chit and all that. We do not know what the position is. I demand, therefore, that the report should be laid on the Table of the House. In fact, all of us should get a copy each. If it is not possible, at least one copy of the report should be laid on the Table of the House, so that the public is not confused. Propaganda is being built up on the findings of the enquiry committee headed by Mr. Justice A.K. Sarkra.